[Dr. Sarojini Mahishi]

and I request the House to accept this Bill unanimously.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill to provide for the extension of the duration of the present Legislative Assembly of the State of Kerala, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, there are no amendments. I will put the clauses to the vote.

Now, the question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That clause 1, Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. SAROJINI MAHISHI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.35 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: CONSTITUTION OF A COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGE

MR. CHAIRMAN: We shall now take up the Statutory Resolution regarding Committee on Official Language.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): I beg to move the following Resolution.—

"Whereas under sub-section (1) of section 4 of the Official Languages Act, 1963, after the expiration of ten years from the date on which section 3 comes into force, there shall be constituted a Committee on Official Language, on a resolution to that effect being moved in either House of Parliament with the previous sanction of the President and passed by both Houses; and whereas section 3 of the aforesaid Act has come into force on 26th January, 1965 and the previous sanction of the President has been obtained for moving the resolution;

This House resolves that a Committee on Official Language shall be constituted."

सभापति जी, अभी तक तो आप कोकोनट ट्रीज और कोकोनट की बातें सुन रहे थे, अब मैं उससे कुछ हट कर जबानदानी की बातें कर रहा हूं। 1963 में राज-भाषा का बिल पास किया गया था, उस के बाद उसको 26 जनवरी, 1965 से लागू किया गया। उस की धारा 4, सब-सैक्शन 1 के अन्तर्गत यह कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद एक पार्लियामेन्ट्री कमेटी का गठन किया जायगा जिसमें 20 मेम्बर लोक सभा के और 10 मेम्बर राज्य सभा के होंगे। इसीलिए मैं इस रेजोल्यूशन को पेश कर रहा हूं।

सभापति जी, आपको मालूम होगा कि पिछले सेशन में भी इस सदन में मैं इसरे जौल्यूशन को ला रहा था। कई रोज तक यह आर्डर पेपर पर रहा। और अगर उस वक्त कमेटी का गठन हो गया होता तो आज तक इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ काम हो गया होता

हालांकि हम बहुत चाहते थे, लेकिन बद-किस्मती से उस सेशन के आखिरी दिन हमारे सामने बैठे हुए दोस्तों ने एक नो-कान्फिडेंस का मोशन ला कर इस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया । इस कारण इसमें तीन साल की देरी हुई और अब मुझे यह रेजोल्यूशन लाना पड़ा ।

इस कमेटी की जो रिपोर्ट आयेगी, वह प्रेसिडेन्ट के पास जायगी, प्रेसिडेन्ट उसको दोनों सदनों में रखेंगे । सारे राज्यों को भी वह रिपोर्ट भेजी जायगी । उसके बाद राज्यों से जो सिफारिशें आयेंगी और उनके जो विचार होंगे यानी हमारे दोनों सदनों के जो विचार होंगे, वे फिर प्रेजिडेन्ट के पास भेजे जायेंगे । प्रेजिडेन्ट साहब उन पर गौर करेंगे और उसमें जो उचित होगा, उन के बारे में अपने आदेश देंगे, ताकि राजभाषा को आगे बढ़ाने में जो कमियां रह गई हैं, उन को दूर किया जा सके ।

इस सिलसिले में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बहुत पहले से ही और 1968 से खास तौर से इसको आगे बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने जितना भी हो सका काम किया है । इस वक्त तक, यानी लगभग 20 वर्षों में, हम ने 3 लाख के करीब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हिन्दी की तालीम दी है, ताकि वे हिन्दी में काम कर सकें । आपको यह जान कर खुशी होगी कि 1970 में सिर्फ 6 हजार पत्र हिन्दी में आए थे, लेकिन 1974 में 26 हजार के करीब पत्र आए जो हिन्दी में थे । 1970 में 176 सैक्शन्ज थे जो हिन्दी में काम करते थे, लेकिन 1974 में 534 के करीब ऐसे सैक्शन्ज थे जिनमें हिन्दी में कार्य होता था । अब कोई भी मंत्री यदि चाहे तो कैबिनेट को नोट हिन्दी में भेज सकता है और हमारी जितनी कैबिनेट मीटिंग्ज होती हैं उन के मिनट्स दोनों भाषाओं में—हिन्दी और अंग्रेजी में—मिलते हैं । इसके अलावा सब से बड़ी बात यह हुई है कि अभी अभी हाल में प्रधान मंत्री जी ने स्पेशली आर्डर किया है कि यहां पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट आफ़ लैंग्वेज बनाया जाय, उस डिपार्टमेंट का एक अलग सेक्रेटरी हो । लिहाजा अभी हाल में एक सेपरेट डिपार्टमेंट आफ़ लैंग्वेज बनाया गया है ।

इसके साथ साथ जितने भी हिन्दी की पोस्टों पर लोग काम कर रहे हैं अलग अलग मंत्रालयों में उनके लिए एक सेन्ट्रलाइज्ड काडर बनाया जा रहा है ताकि उन का जो कार्य हो उसमें कोआर्डिनेशन हो और ठीक तरह से काम हो सके ।

इसके अलावा कलकत्ता और मद्रास में एक एक नेशनल लाइब्रेरी है, लेकिन दिल्ली में कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी । इसके लिये जो हमारी भारतीय भाषायें हैं, उन के लिए तुलसी सदन नामक भवन में दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जिसमें हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं की पुस्तकें लोगों को पढ़ने के लिये मिल सकती है ।

इसके अलावा हर मंत्रालय के साथ एक एडवाइजरी कमेटी लगी हुई है जो देखती है कि उन मंत्रालयों में पूरी तरह से गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन हो रहा है कि नहीं । उसमें भी पार्लियामेंट के सदस्य मेम्बर्स हैं । शुरू में चार मंत्रालयों में एडवाइजरी कमेटियां थीं, इसके बाद सात मंत्रालयों में हुई । और अभी हाल में हम ने फैसला किया है कि 9 और मंत्रालयों में इसी तरह की कमेटियां बना दी जाएं ताकि वह देखें कि जो जो आदेश दिये जाते हैं उन पर पूरी तरह से अमल होता है कि नहीं ।

इसके अलावा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक सेन्ट्रल हिन्दी कमेटी पूरी तरह से काम कर रही है जो यह देखती है कि हिन्दी के बढ़ावे में कोई कमी न हो । लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

[श्री ओम मेहता]

जहां हिन्दी के बढ़ावे की हम बात कर रहे हैं वहां जो अहिन्दी भाषा भाषी हैं उनको किसी किस्म की चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकि वह सेन्टर के साथ अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार कर सकते हैं और अंग्रेजी में ही उनको जवाब भी दिये जाते हैं।

तो मैं फिर यही कहूंगा कि सरकारी काम काज में हिन्दी के इस्तेमाल के बारे में जो भी डायरेक्शन्स दिये गये हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जायेगी और यह कमेटी देखेगी कि उन डायरेक्शन्स का कहां तक पालन हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा यह रेजोल्यूशन राजभाषा ऐक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पेश किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरा साथ देगा और इस रेजोल्यूशन को पास करेगा।

MR. CHAIRMAN: There are no speakers. I will put the question..

DR. RANEN SEN (BARASAT): I just want to ask a question. There is one clarification which is required.

DR. HENRY AUSTIN (ERNAKULAM): It is a matter of importance; we want to have some clarification only

DR. RANEN SEN: Sir, the Minister in his speech said that there is this National Library at Delhi. He said, not only Hindi books, but other language books are available. Will he tell us, how many books other than Hindi are there, can he give some rough idea? What I heard is that this is mainly a Hindi Library, very few books of other languages are available there.

SHRI OM MEHTA: It is under the Ministry of Education. I do not know the exact number of books. But it is a National Library for all Indian languages. It cannot be that only Hindi books are there. It is governed by the Act under which all the publishers are required to send one or two copies. Therefore, books of those other Indian languages will also be available there.

DR. HENRY AUSTIN: This is just by way of clarification. Although there is contrary or perhaps not very favourable trend across our borders in Tamilnadu, Kerala has been focussing attention in regard to the popularisation of Hindi and we have taken several steps. The universities and schools are popularising it. But the problem is this. I am getting very many letters from my constituency particularly from the city of Cochin from trained Hindi teachers. But they are not getting any jobs. There is no way of absorbing these trained teachers. There is so much of enthusiasm for Hindi both at the governmental and non-governmental levels; But, there should be some machinery of absorbing these teachers and others trained in Hindi.

SHRI OM MEHTA: I shall look into the matter.

MR CHAIRMAN: Now, the question is:

"Whereas under sub-section (1) of section 4 of the Official Languages Act, 1963, after the expiration of ten years from the date on which section 3 comes into force, there shall be constituted a Committee on Official Language, on a resolution to that effect being moved in either House of Parliament with the previous sanction of the President and passed by both Houses: and whereas section 3 of aforesaid Act has come into force on 26th January, 1965 and the previous sanction of the President has been obtained for moving the re-

solution; This House resolves that a Committee on Official Language shall be constituted."

The motion was adopted.

17.16 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGE

MR. CHAIRMAN: We now go to item No. 22—Contingent Notice of Motion for Election to Committee. Shri Mehta.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): "That in pursuance of sub-section (2) of section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, twenty members from amongst themselves to be members of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon in accordance with sub-section (3) of Section 4 of the said Act."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That in pursuance of sub-section (2) of Section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in accordence with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, twenty members from amongst themselves to be members of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon in accordance with sub-section (3) of Section 4 of the said Act."

The motion was adopted.

17.17 hrs.

BANKING SERVICE COMMISSION BILL

MR. CHAIRMAN: We now go to the next item of legislative business. Shrimati Rohatgi.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): I beg to move:

"That the Bill to provide for the establishment of a Commission for the selection of personnel for appointment to services and posts in certain banking institutions and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.".

Sir, the Bill for consideration seeks to set up a Service Commission for recruitment of personnel for the public sector banks. The objects and reasons accompanying the Bill set out the purpose, but as this is an important piece of legislation, I wish to place before the House the considerations that have weighed with the Government in bringing forward this legislation.

Manpower planning and development have assumed increasing importance after nationalisation of the major banks. The task before the public sector banks is to take banking to unbanked areas and service the diverse productive activities which had been traditionally outside the purview of the organised banking sector. Without the support of qualified manpower, the public sector banks will be greatly handicapped in fulfilling their basic tasks. Every